



62

नवीन प्रमाण . 3410/2017

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश, ग्वालियर  
निगरानी मिण्डायू-राजस्व 3410  
प्रकरण क्रमांक 12087 निगरानी

सुरेश पुत्र मंगल सिंह, निवासी गढ़ा मौहल्ला,  
वाह नम्बर 13, तौहद, तैहसील गौहद, जिला मिह  
(मध्य प्रदेश) ।

----- प्रार्थी

बिराध

मध्य प्रदेश शासन ----- प्रतिप्रार्थी

निगरानी बिराध आदेश तैहसीलदार महोदय, गौहद दिनांकी 30-5-17,  
अन्तर्गत धारा 10 मध्य प्रदेश मू-राजस्व संस्था, 1844E प्रो क्रो 73186-17-  
ब-12 ।

श्रीमान् जी,

निगरानी का आवेदन पत्र निम्न आधारों पर प्रस्तुत है :-

- 1- यह कि, तैहसीलदार महोदय की विवादित वाशा कानूनन सही नहीं है ।
- 2- यह कि, प्रकरण में धारा 124 मू-राजस्व संस्था के प्रावधानों एवं इस धारा के अधीन बने नियमों का अनुपालन न होने से, की गई सीमांकन की कार्यवाही निरस्ती योग्य है ।
- 3- यह कि, कानूनन प्रतिकेदन कोई साध्य नहीं है ।
- 4- यह कि, राजस्व निरीक्षक महोदय द्वारा प्रस्तुत प्रतिकेदन पर सीमांकन की कार्यवाही की न तो पुष्टि ही की गई है, और न ही उसे अमान्य ही किया गया है । ऐसी स्थिति में प्रकरण की कार्यवाही समाप्त किये जाने में मूल की गई है ।

5- यह कि, सीमांकन प्रतिकेदन पर प्रार्थी को न तो वापस प्रस्तुत  
क्रमशः ---2


दिनांक 21-9-17 को  
श्री. राम. को लक्ष्मी  
कोर्ट द्वारा सुनवाई  
है. 29/9/17

29-9-17

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - तीन/निगरानी/भिण्ड/भू.रा./2017/3410

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5-12-18	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री एस.के. अवस्थी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 26-2-19 को कलेक्टर, जिला भिण्ड के समक्ष उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: right;">   <b>प्रशासकीय सदस्य</b> </p>	

3